



रजि. नं. एन. डब्ल्यू. / एन. पी. 890

सिद्धार्थ नं० डब्ल्यू पी०-६१

सिद्धार्थ नं० एन. डब्ल्यू. पी. ८९०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

संख्यक, शुकवार, 8 अगस्त, 1997

आवण 17, 1919 तक सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुधात-1

संख्या 1130/संवह-वि-1-1 (क)-11-1997

संख्यक, 8 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 7 अगस्त, 1997 को अनुसूचि प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचवाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1997)

[यह उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अद्यतन संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के संविधानोत्पत्त अर्थ में विधिलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

कम संख्या।

(2) भारत के और 8 देश दिनांक को प्रवृत्त होगी, यथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस विधिय निम्न करे, यथा 8 के खण्ड (क) और खण्ड (घ) का उपखण्ड (दक) 1 दिनांक, 1994 को प्रवृत्त हुआ यथा यथा और केव उपखण्ड सुरक्षित प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश 2--उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, ऐक्ट संख्या 15 का धारा 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--
 1948 की धारा 2 का खण्ड (ख) "ख" किसी माल के सम्बन्ध में, "निर्माता" का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(एक) ऐसा व्यापारी जो ऐसी साहकिलें बेचता है जिसके पुर्जे पूर्णतया अलग-अलग हैं;

(दो) ऐसा व्यापारी जो किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, जो ऐक्ट की धारा 4, 4-क और 4-कक के अधीन छूट प्राप्त बिक्री से भिन्न, अपनी बिक्री पर कर का देनदार न हो, खरीद करता है।

धारा 3-क का संशोधन 3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सव्व से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :--

"(ग) सभी प्रकार की स्ट्रिट और स्ट्रिटवय वादाज जिसमें मियाहल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल और अल्कोहल सम्मिलित है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर या ऐसे अन्य ऐच्छल स्थल पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, बीस प्रतिशत की दर पर या छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा।"

नई धारा 3-कक का बढाया जाना अर्थात् :-- 4--मूल अधिनियम की धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जायगी,

"3-कक--धारा 3-क और 3-घ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और ऐसे निर्वन्दनों और शर्तों के अधीन बिक्री या खरीद करते हुए ऐसी उसमें विनिदिष्ट की जाय, घोषित माल से भिन्न किसी के सभी स्थलों माल या माल के बगैरे की राज्य के भीतर बिक्री या खरीद के सभी पर कर का स्थलों पर धारा 3-क या 3-घ के अधीन जारी विज्ञप्तियों में उद्ग्रहण विनिदिष्ट दरों पर और यदि कर की दर के सम्बन्ध में ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो तो धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में यथाविनिदिष्ट बाठ प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी :

प्रतिशय यह है कि, विक्रय धन के ऐसे भाग पर जिस पर राज्य के भीतर पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद पर कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, या पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद के ऐसे विक्रय धन पर जिस पर ऐक्ट के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन छूट दे दी गयी हो, कोई कर देय नहीं होगा।"

धारा 3-ककक का संशोधन 5--मूल अधिनियम की धारा 3-ककक में, (क) शब्द "उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तु के खण्ड (एक) में शब्द "धारा 3-ककक के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-घ का संशोधन 6--मूल अधिनियम की धारा 3-घ में, उपधारा (2) में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, शब्द "ख" के उपखण्ड (एक) में, शब्द "मूल्य" के स्थान पर शब्द "विक्रय मूल्य" रख दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1989 को गले रवे समझी जायेंगे।

धारा 3-छ का संशोधन 7--मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (2) में शब्द "विद्युत ऊर्जा" के स्थान पर शब्द "विद्युत ऊर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 की संशोधन 8--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) खण्ड (क) में शब्द "नमक" के स्थान पर शब्द "नमक प्रसंस्कृत और (ख) खण्ड (क) में शब्द "नमक" के स्थान पर शब्द "नमक प्रसंस्कृत और

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में शब्द "या सुगन्धित पानी" के स्थान पर शब्द "सुगन्धित पानी या कौंक से या अन्य प्रकार से सोल बन्द पात्र में या कौंसूल में बचे जाने वाला निर्मित या प्रवस्कृत पानी" रख दिये जायेंगे।

धारा 4-क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4-क में,—

(क) उपधारा (1) में—

(एक) शब्द "वारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करने वाले किसी नई इकाई में, या किसी विद्यमान इकाई में जो पंचवर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय विस्तार, विविधोत्तरण, आधुनिकीकरण और विविध बन्द-दोषोपशान्त या उनमें से किसी एक में पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी-विनिधान करने में निमित्त माल के सम्बन्ध में छूट या उसकी दरों में कमी, राज्य सरकार द्वारा दत्त निमित्त समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है।"

(ख) उपधारा (2-ख) में—

(एक) शब्द "यदि उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" के स्थान पर शब्द "यदि विक्रय, लाइसेंस, प्रवन्ध अधिग्रहण द्वारा या किसी अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बड़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"अधतर प्रतिबन्ध यह है कि कर की देनदारी के प्रयोजन के लिए ऐसा निर्माता और उत्तराधिकारी निर्माता धारा 3-गू के अधीन हस्तान्तर करों और हस्तान्तरित माना जायगा।"

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (क) में शब्द "उक्त" उपधारा में निरदिष्ट सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के सुसंगत दिनांक में छः मास के भीतर" के पश्चात् शब्द "या उक्त उपधारा के अधीन जारी विज्ञप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर" रख दिये जायेंगे;

(घ) स्पष्टीकरण (5) में—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "जिसकी उत्पादन क्षमता" के स्थान पर शब्द और शब्द "उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यथाउपरोक्त के सिवाय जिसकी उत्पादन क्षमता" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बड़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) जो उसी जिले के भीतर स्थापित की गई हो जिसमें वर्तमान औद्योगिक इकाई स्थापित हो।"

मूल अधिनियम की धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :—

धारा 4-कक का प्रतिस्थापन

(कक) धारा 4-क के अन्तर्गत दी गयी किसी वीत् के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समझौता हो या किसी कतिपय औद्योगिक उपक्रम की किसी स्वायत्त संस्था द्वारा पारित आदेश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण कर दिया गया हो तो वह विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट और शर्तों के अधीन ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को पन्द्रह वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए छूट प्रदान कर सकता है, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय।"

धारा 4-ख का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

“(5) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण प्रत्यया कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी एक-द्वारक ऐसी घनराशि का, जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करें, देनदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे माल की विक्री पर या खरीद पर देय कर की घनराशि और इस ऐक्ट के अधीन अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की घनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की घनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।”

“(6) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कारित सामग्री से निर्मित माल या ऐसी वैकल्पिक सामग्री के साथ एक किए जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा व्यापारी इस धारा के अधीन ऐसे माल की विक्री पर या खरीद पर देय कर की घनराशि और ऐसे माल की विक्री पर या खरीद पर देय प्रतिशत की दर से घातलित कर की घनराशि के अन्तर के अन्तर्गत घनराशि का देनदार होगा।”

धारा 5 का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“5 (1) वहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सीमाहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह विनियम द्वारा और ऐसी शर्तों और शर्तियों पर कर दिखानों के अधीन रखे हुए, जैसी विनिर्दिष्ट हो,—

- (अ) किसी भाषा के विषय या अन्य पर, या
- (ब) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसे माल जो उपर्युक्त विनियम में विनिर्दिष्ट किए जायें, के विक्रय या क्रय पर,

किसी विनिर्दिष्ट स्थल पर लंबाई मने कर की पूरी घनराशि तक छूट दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन छूट विनियम के दिनांक के पूर्व के दिनांक से दी जा सकती है।

धारा 8 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) के अन्वयेकरण में शब्द, अथवा अथवा “धारा 3-ख के अधीन” के स्थान पर शब्द अथवा अथवा “धारा 3-ख या धारा 4-ख की उपधारा (6) के अधीन” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2-क) में—

(एक) शब्द “राज्य सरकार” के स्थान पर शब्द “कमिश्नर” रख दिये जायेंगे;

(दो) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक शब्द बढ़ा दिये जायेंगे—

“प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत के विनियम की शर्त से कमिश्नर ऐसे निर्याता के, जिसकी लागू शर्तों के अन्वये प्रारम्भ करने की दिनांक 1 अक्टूबर, 1950 को उसके पश्चात् पड़ता हो, आर्सेनाल-पत्र पर धारा 4-क के अधीन छूट के बजाय स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिनियम स्वीकार कर सकता है और वह अधिनियम स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1953 द्वारा अस्थापित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1949 नियम 43 के अन्वये लागू होंगे।”

14--मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

धारा 9 का संशोधन

(क) उपधारा (1-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी,

अर्थात् :-

“(1-ख) इस ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों या इस ऐक्ट के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किए गए इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, विक्रय घन या क्रय घन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की घनराशि, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो”;

(ख) उपधारा (3-क) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में--

(एक) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

“(1) इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत न किया जाय;”

(दो) खण्ड (2) निकाल दिया जायगा;

(ग) उपधारा (7) का स्विकारण निकाल दिया जायगा।

15--मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

धारा 10 का संशोधन

(क) उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (1) में शब्द और अंक “धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “धारा 9 की उपधारा (1-ख) के अधीन” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

“(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की घनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो;”

16--मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (9) निकाल दी जायगी।

धारा 13-क का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “ऐसे वर्ष के अन्त से तीन वर्ष या 31 मार्च, 1996 जो भी पश्चात्पूर्वी हो” के स्थान पर शब्द और अंक “ऐसे वर्ष के अन्त से दो वर्ष, या 31 मार्च, 1998 जो भी पश्चात्पूर्वी हो”; रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

18--(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निदिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्राज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश
समाचारण
गजट
अगस्त 7
1997

No. 1130 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 11-97

Dated Lucknow, August 8, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 7, 1997.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT)
ACT, 1997

(U.P. Act No. 11 of 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1997.

(2) Sections 5 and 8 shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf, clause (a) and sub-clause (i) of clause (d) of section 9 shall be deemed to have come into force on December 1, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of
section 2 of
U. P. Act no. 15
of 1948

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (ee) the following clause shall be substituted, namely :—

“(ee) ‘manufacturer’ in relation to any goods means the dealer who makes the first sale of such goods in the State after their manufacture and includes,—

(i) a dealer who sells bicycles in completely knocked down form;

(ii) a dealer who makes purchases from any other dealer not liable to tax on his sale under the Act other than sales exempted under sections 4, 4-A and 4-AAA.”

Amendment of
section 3-A

3. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely :—

“(c) on the turnover of spirits and spirituous liquors of all kinds including methyl alcohol and motor spirit, diesel oil and alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, at the point of sale by the manufacturer or importer or such other single point, as the State Government may, by notification, declare at the rate of twenty per cent or at such rate not exceeding twenty six per cent, as the State Government may, by notification declare.”

Insertion of new
section 3-AA

4. After section 3-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“3-AA. Notwithstanding anything contained in section 3-A and 3-D, the State Government may, by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein, levy tax at all points of sale or purchase within the State or any goods or class of goods, other than declared goods, at the rates specified in the notifications issued under section 3-A or section 3-D

and if no such notification has been issued in respect of rate of tax, then at the rate of eight per cent as specified in clause (e) of sub-section (1) of section 3-A :

Provided that no tax shall be payable on the part of the turnover on which tax has already been paid on the preceding sales or purchases within the State or on the turnover of preceding sales or

Levy of tax
on all points
of sale or pur-
chase

purchases as has been exempted under any other provisions of the Act."

5. In section 3-AAAA of the principal Act,—

(a) for the words "at the point of sale to consumer" the words "under this Act" shall be substituted;

(b) in clause (i) of the proviso for the words "under section 3-AAA" the words "under this Act" shall be substituted.

Amendment of section 3-AAAA

6. In section 3-F of the principal Act, in sub-section (2), in sub-clause (i) of clause (a) and in sub-clause (i) of clause (b) for the word "value" the words "sales value" shall be substituted and be deemed to have been substituted on September 13, 1985.

Amendment of section 3-F

7. In section 3-G of the principal Act, in sub-section (2), for the words "electrical energy" the words "electrical energy and Railway diesel locomotive engine" shall be substituted.

Amendment of section 3-G

8. In section 4 of the principal Act,—

(a) in clause (a) for the word "salt" the words "salt excluding processed and branded salt" shall be substituted;

Amendment of section 4

(b) in Explanation, in clause (a) for the words "or scented water" the words "scented water or manufactured or processed water sold in container sealed with a cork or otherwise or in capsule;" shall be substituted.

9. In section 4-A of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "twelve years" the words "fifteen years" shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 4-A

"Provided that in respect of goods manufactured in a new unit having a fixed capital investment of fifty crore rupees or more or in an existing unit which may make fixed capital investment of fifty crore rupees or more in expansion, diversification, modernisation and backward integration or in any one of them, within such period not exceeding five years as may be specified in the notification, the exemption from or reduction in the rate of tax may be granted after considering the recommendation of a Committee constituted by the State Government in this behalf."

(b) in sub-section (2-B),—

(i) for the words "if he is succeeded by another manufacturer, such successor manufacturer may," the words "if he is succeeded by another manufacturer, by means of sale, licence, contract, lease, managing agency or in any other manner such successor manufacturer may," shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that such manufacturer and successor manufacturer for the purpose of liability of tax shall be treated as the transferor and the transferee under section 3-C."

(c) in sub-section (5), in clause (a) after the words "facility referred to in that sub-section" the words "or within six months from the date of notification issued under that sub-section" shall be inserted;

(d) in Explanation (5),—

(i) in clause (c) for the words "the production capacity whereof" the words and figure "the production capacity whereof except as provided in the proviso to sub-section (1)" shall be substituted;

(ii) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) which has been established within the same district in which the existing industrial unit is established."

Substitution of
section 4-AAA

10. For section 4-AAA of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“4-AAA Notwithstanding anything contained in section 4-A, where the State Government is satisfied that certain industrial undertaking has been shifted from one place to another place on account of the order passed by any court, it may, by notification, grant such concession or exemption from tax for such period not exceeding fifteen years and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein to such industrial undertaking.”

Amendment of
section 4-B

11. In section 4-B of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(5) Where a dealer in whose favour a recognition certificate has been granted under sub-section (2) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate under this section or, as the case may be, without payment of tax and has used such goods for a purpose other than that for which the recognition certificate was granted or has otherwise disposed of the said goods, such dealer shall be liable to pay as penalty such amount as the assessing authority may fix which shall not be less than the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act but not exceeding three times the amount of such difference.

(6) Where a dealer in whose favour a recognition certificate has been granted under sub-section (2) has purchased any goods after payment of tax at concessional rate under this section, or as the case may be, without payment of tax and the goods manufactured out of such raw materials or processing materials or manufactured goods after being packed with such packing material are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the State or in the course of inter State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, such dealer shall be liable to pay an amount equal to the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this section and the amount of tax calculated at the rate of four per cent, on the sale or purchase of such goods.”

Substitution of
section 5

12. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“5 (1) Where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a rebate up to the full amount of tax levied on any specified point on,—

- (a) the sale or purchase of any goods, or
- (b) the sale or purchase of such goods, by such person or class of persons as may be specified in the said notification.

(2) The rebate under sub-section (1) may be allowed with effect from a date prior to the date of the notification.”

Amendment of
section 8

13. In section 8 of the principal Act,—

(a) in Explanation to sub-section (1) for the words, figure and letter “under section 3-B” the words, figures and letters “under section 3-B or sub-section (6) of section 4-B” shall be substituted;

(b) in sub-section (2-A),—

(i) for the words “the State Government” the words “the Commissioner” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that on and after the commencement of the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1997 the Commissioner may on the application of a manufacturer

having a small scale industry the date of starting production of which falls on or after April 1, 1990, grant, in a lieu of exemption under section 4-A, moratorium for payment of the admitted tax and the provision of rule 43 of the Uttar Pradesh Trade Tax Rules, 1948 as amended by the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Rules, 1993 shall apply for granting such moratorium."

14. In section 9 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1-B) the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of section 9

"(1-B) No appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases, as the case may be, admitted by the appellant in the returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Act, whichever is greater.";

(b) in section (3-A), in the proviso,—

(i) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) no application under clause (b) of this sub-section shall be entertained unless it is filed alongwith the memorandum of appeal under sub-section (1);"

(ii) clause (ii) shall be omitted.

(c) in sub-section (7) the Explanation shall be omitted.

15. In section 10 of the principal Act,—

(a) in the proviso to sub-section (6), in clause (i) for the words and figures "under sub-section (1) of section 9" the words, figures and letter "under sub-section (1-B) of section 9" shall be substituted;

Amendment of section 10

(b) in sub-section (10) for sub-clause (i) of clause (a) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(i) by a bench of two members, where such order is passed by an Additional Commissioner (Appeals) or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds fifty thousand rupees;"

16. In section 13-A of the principal Act, sub-section (9) shall be omitted.

Amendment of section 13-A

17. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2) for the words and figures "three years from the end of such year or March 31, 1996 whichever is later" the words and figures "two years from the end of such year or March 31, 1998 whichever is later" shall be substituted.

Amendment of section 21

18. (1) The Uttar Pradesh Tax (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal; anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

गी ०२२०५००००—२००० १३५ स० वि००—(१६७)—१९९७—८५० (मेक ०) ।